



डकिडगि गुड गवरनेस

प्रलिमिंस के लयि:

[अटल बहिरि वाजपेयी](#) और [सुशासन दविस](#), [वशिव बैक](#), भर्षटाचार अनुभूति सूचकांक 2022, [केंद्रीय लोक शकियत नविरण और नगिरानी प्रणाली](#), [सूचना का अधकिर अधनियम](#), [73वाँ और 74वाँ सांविधानकि संशोधन](#), [युनफाइड पेमेंट्स इंटरफेस](#), [आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम](#), नागरकि चार्टर

मेन्स के लयि:

भारत में शासन व्यवस्था से संबंधति प्रमुख मुद्दे, भारत में सुशासन से संबंधति प्रमुख पहल

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यो?

25 दसिंबर को भारत ने पूर्व प्रधानमंत्री [अटल बहिरि वाजपेयी](#) की जयंती के अवसर पर [सुशासन दविस](#) मनाया ।

- वार्षकि तौर पर मनाया जाने वाला यह दविस शासन व्यवस्था तथा सरकारी प्रक्रियाओं में उत्तरदायतिव के संबंध में नागरकि जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करता है ।
- इस अवसर पर एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशकिषण (Integrated Government Online Training- iGOT) कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर तीन नई सुविधाओं, [माई iGOT](#), [बलेंडेड प्रोग्राम](#) और [क्यूरटेड प्रोग्राम](#) का शुभारंभ कया गया ।

सुशासन क्या है?

- परिचय:
 - शासन व्यवस्था उन प्रक्रियाओं, प्रणालियों तथा संरचनाओं को संदर्भति करती है जनि के माध्यम से संगठनों, समाजों अथवा समूहों को नरिदेशति, नयित्तरति एवं प्रबंधति कया जाता है ।
 - [सुशासन](#) को मूल्यों के एक समूह के रूप में परिभाषति कया गया है जसि के माध्यम से [एकसार्वजनकि संस्थान सार्वजनकि मामलों का संचालन करती है तथा सार्वजनकि संसाधनों का प्रबंधन](#) इस तरह से करती है जो मानवाधिकारों, वधिसिम्मत शासन एवं समाज की ज़रूरतों के अनुरूप हो ।
 - [वशिव बैक](#) सुशासन को उन परंपराओं तथा संस्थानों के संदर्भ में परिभाषति करता है [जनिके द्वारा कसी देश में प्राधिकार का प्रयोग कया जाता है](#) । इनमें शामिल हैं:
 - वह प्रक्रिया जसिके द्वारा सरकारों का चयन, नगिरानी तथा प्रतस्थिपन कया जाता है ।
 - प्रभावी नीतियों को प्रभावी ढंग से तैयार कर उन्हें कार्यान्वति करने की सरकार की क्षमता ।
 - उन संस्थानों के प्रतनागरिकों तथा राज्य का सम्मान जो उनके बीच आर्थकि एवं सामाजकि संबंधों को नयित्तरति करते हैं ।

सुशासन के मूल सदिधांत:



//

वश्वव्यापी शासन संकेतक क्या है?

- वश्व बैंक की वश्वव्यापी शासन संकेतक परयोजना शासन के छह मूलभूत उपायों के आधार पर 200 से अधिक देशों का मूल्यांकन करती है।
- छह संकेतक हैं:
 - अभवियक्ति और दायतिव
 - राजनीतिक स्थरिता और हसिा का अभाव
 - सरकारी प्रभावशीलता
 - नयिामक गुणवत्ता
 - [वधिका शासन](#)
 - भ्रषुटाचार पर नयित्रण

भारत में शासन से संबंधति प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- भ्रषुटाचार और नौकरशाही अक्षमता: [भ्रषुटाचार बोध सूचकांक- 2022](#) में रश्वतखोरी और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के बारे में चतिाओं को उजागर करते हुए भारत 180 देशों में 85वें स्थान पर था।
- असमानता और सामाजिक बहषिकार: आर्थिक वकिस के बावजूद, अमीर और गरीब के बीच बहुत बड़ा अंतर बना हुआ है। वर्ष 2022 की ऑक्सफैम रपिर्ट से पता चला है कि भारत में सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की 40% से अधिक संपत्ति है, जबकि निम्न स्तरीय 50% के पास सरिफ 3% संपत्ति है। इससे स्वास्थय देखभाल, शकिषा और अवसरों तक पहुँच में असमानताएँ बढ़ती हैं।
- नीतियों और योजनाओं का अप्रभावी कार्यान्वयन: कई अच्छे इरादे वाले सरकारी कार्यक्रम खराब नषिपादन के कारण प्रभावति होते हैं, जसिसे उनका प्रभाव सीमति हो जाता है।
 - वर्ष 2023 में CAG ने [आयुषमान भारत योजना](#) में अनयिमतिताएँ पाई, इसके अलावा CAG की एक अन्य रपिर्ट में झारखंड में पुरुषों को वधिया पेंशन के हसुतांतरण पर प्रकाश डाला गया है।
- अपर्याप्त न्यायिक अवसरचना: भारत के न्यायालय बड़े पैमाने पर लंबति मामलों के बोझ से दबे हुए हैं, जसिसे वविाद समाधान और न्याय तक पहुँच में

देरी हो रही है, खासकर हाशिये पर रहने वाले लोगों को।

- वर्ष 2023 में **सर्वोच्च न्यायालय** में **80,000 से अधिक मामले लंबित** थे, जिससे कानूनी सहायता तक समय पर पहुँच को लेकर चर्चाएँ बढ़ गईं।

- **पर्यावरणीय गतिरोध और जलवायु परिवर्तन:** भारत को वायु प्रदूषण, जल की कमी और वनों की कटाई जैसी प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। **वर्ष 2023 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट** ने पर्यावरणीय नयियों के कमजोर प्रवर्तन को उजागर करते हुए **कई भारतीय शहरों को विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित शहरों में स्थान दिया है।**
- **राजनीतिक ध्रुवीकरण और जवाबदेही का अभाव:** बढ़ते पक्षपात और चुनावी लाभ पर ध्यान कभी-कभी भारत में दीर्घकालिक नीति नियोजन और लोक कल्याण पर भारी पड़ जाता है।

भारत में सुशासन से संबंधित प्रमुख पहल क्या हैं?

- **पारदर्शिता और दायित्व:**
 - **सूचना का अधिकार अधिनियम (2005):** यह अधिनियम नागरिकों को सरकारी जानकारी तक पहुँचने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार को कम करने का अधिकार देता है।
 - **केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और नगिरानी प्रणाली (CPGRAMS):** सरकारी विभागों के खिलाफ शिकायतें दर्ज करने और उन पर नज़र रखने के लिये ऑनलाइन मंच।
 - **ई-गवर्नेंस पहल:** बढ़ी हुई दक्षता और कम मानवीय संपर्क के लिये सरकारी सेवाओं (जैसे, ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग, संपत्ति पंजीकरण) का डिजिटलीकरण।
 - **सटीक चार्टर:** सरकारी एजेंसियों द्वारा सेवा मानकों और समय-सीमा के प्रति प्रतिबद्धता, जवाबदेही बढ़ाना।
- **नागरिक भागीदारी और सशक्तीकरण:**
 - **MyGov प्लेटफॉर्म:** यह नागरिकों को नीतिगत चर्चाओं में भाग लेने, विचार प्रस्तुत करने और सरकार को प्रतिक्रिया प्रदान करने में सक्षम बनाता है।
 - **ग्राम सभाएँ:** ग्रामीण क्षेत्रों में सहभागी निर्णय लेने के लिये ग्राम-स्तरीय बैठकें।
 - **शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009):** समुदायों को सशक्त बनाते हुए 6-14 आयु वर्ग के बच्चों के लिये मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है।
- **वर्केंद्रीकरण और स्थानीय शासन:**
 - **73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन:** स्थानीय लोकतंत्र को बढ़ावा देते हुए वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के साथ पंचायतों (ग्राम परिषदों) तथा नगर पालिकाओं को सशक्त बनाना।
 - **आकांक्षी जिला कार्यक्रम:** भौगोलिक रूप से वंचित 112 जिलों में सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
 - **स्मार्ट सटी मशिन:** बेहतर जीवन के लिये बुनियादी ढाँचे और प्रौद्योगिकी समाधान के साथ 100 शहरों का विकास।
- **अन्य पहल:**
 - **डिजिटल इंडिया कार्यक्रम:** इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी तक व्यापक पहुँच के साथ भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलना है।
 - **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण:** बैंक खातों के माध्यम से सीधे लाभार्थियों को सब्सिडी और लाभ का हस्तांतरण, रसिया और भ्रष्टाचार को कम करना।
 - **आधार कार्ड:** नागरिकों के लिये विशिष्ट पहचान प्रणाली, वित्तीय समावेशन और सेवा वितरण को बढ़ावा देना।
 - **दवाला और दवालापन संहिता (2016):** यह खराब ऋण की समस्या को हल करने और व्यापार पुनरुद्धार की सुविधा प्रदान करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती है।
 - **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI):** भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नगिम (NPCI) द्वारा विकसित त्वरित वास्तविक समय मोबाइल भुगतान प्रणाली।
 - यह एकल मोबाइल एप का उपयोग करके नरिबाध अंतर-बैंक लेन-देन सक्षम बनाता है।

आगे की राह

- **जनडेटा प्लेटफॉर्म: वैयक्तिकृत सेवाओं और नीतिगत निर्णयों में नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी के लिये** ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा समर्थित एक सुरक्षित डेटा प्लेटफॉर्म बनाए जाने की आवश्यकता।
 - इसमें **स्मार्ट गवर्नेंस डैशबोर्ड**, विभिन्न सरकारी विभागों के लिये प्रमुख पहल की पारदर्शिता और पहुँच को बढ़ावा देना शामिल होना चाहिये।
- **नौकरशाही में सुधार: प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, लालफीताशाही को कम करना** और सार्वजनिक सेवा के भीतर व्यावसायिकता तथा जवाबदेही को बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है। **विकास (वेरिबल एंड इमर्सिवि कर्मयोगी एडवांस्ड सपोर्ट) इस दशा में एक आवश्यक कदम होगा।**
- **त्वरित न्यायिक सुधार:** लंबित मामलों का समाधान करके न्यायालय प्रणाली के भीतर बुनियादी ढाँचे और दक्षता में सुधार करना और सभी के लिये न्याय तक त्वरित पहुँच सुनिश्चित करना। **ई-कोर्ट और अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग** इस दशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- **AI-संचालित शिकायत समाधान:** एक AI संचालित प्रणाली विकसित करना जो सार्वजनिक शिकायतों का विश्लेषण, पैटर्न की पहचान करती

है और स्वचालित रूप से उन्हें त्वरति समाधान के लिये संबंधित अधिकारियों को नरिदेशति करती है ।

- नागरकि सहभागति की पुनः कल्पना: शहरी स्थानीय नकियाँ और पंचायतों की देख-रेख में ग्रामीण और शहरी कषेत्रों में समुदाय-आधारति नवाचार प्रयोगशालाएँ स्थापति करना, नागरकिों को सरकारी एजेंसियों के सहयोग से स्थानीय समस्याओं का स्थानीय समाधान खोजने के लिये सशक्त बनाना ।
- भवषियोनमुखी शकिषा पाठयकरम: आलोचनात्मक सोच, डजिटिल साकषरता और डेटा वश्लेषण जैसे कौशल को शकिषा प्रणाली में एकीकृत करना, भवषिय की पीढ़ियों को प्रौद्योगिकी-संचालति शासन परदृश्य में सक्रयि भागीदारी के लिये तैयार करना ।

इसलिये **भारत को सतत वकिस लकष्य (SDG) 16: शांति, न्याय और मज़बूत संस्थानों के साथ संरेखति** करते हुए "न्यूनतम सरकार, अधिकितम शासन" के सिद्धांत का पालन करना चाहयि ।

अटल बहारी वाजपेयी:



- 25 दसिंबर, 1924 को ग्वालियर, जो अब मध्य प्रदेश का हिस्सा है, में जन्मे अटल बहारी वाजपेयी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजनीति में प्रवेश कयि ।
- 1996 और 1999 में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कयि, जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार जनादेश हासलि करने वाले पहले व्यक्तबिने । (वर्तमान में नरेन्द्र मोदी)
 - 9 लोकसभा और 2 राज्यसभा चुनाव जीते, 1994 में भारत के 'सर्वश्रेष्ठ सांसद' का खतिब अरजति कयि ।
- 1994 में पद्म वभ्रिषण प्राप्त हुआ और 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरकि सम्मान, भारत रत्न से सम्मानति कयि गया ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. वभिन्नि स्तरों पर सरकारी तंत्र की प्रभावशीलता और शासन तंत्र में जनसहभागति अन्योन्याशरति होती है । भारत के संदर्भ में इनके

बीच संबंध पर चर्चा कीजिये। (2016)

प्रश्न. 'शासन', 'सुशासन' और 'नैतिक शासन' से आप क्या समझते हैं? (2016)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/decoding-good-governance>

